जयंतीलाल रतनचंद शाह

वी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस

9 अगस्त, 1996

[कुलदिप सिंह, एम. एम. पंची, एन. पी. सिंह, एम. के. मुखर्जी और एस. सागर अहमद, जे. जे।

उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978:एसएस.3 , 4 , 7 और 8.

एस.

उच्च मूल्य के बैंक नोटों की संवैधानिकता 16.1.1978 के बाद वैध मुद्रा नहीं रह गई-भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान करने से छूट दी-आयोजितःप्रभावी रूप से अधिनियम ने राज्य से उच्च मूल्य के बैंक नोट धारकों के कारण सार्वजनिक ऋण को समाप्त या समाप्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप उनकी संपत्ति को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया गया-लेकिन इस बुराई को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम ने अपनी प्रस्तावना में दिए गए उपाय के लिए डी की मांग की थी, अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए था-इसलिए, अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन नहीं था-संपत्ति के इस तरह के अनिवार्य अधिग्रहण के बाद, उच्च मूल्य के बैंक नोट धारकों का अधिकार समाप्त हो गया और गैर-निहित हो गया-इसलिए, अधिनियम के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) का उल्लंघन नहीं हुआ-अधिनियम की धारा 7 और 8 ने ई.

उच्च मूल्य के बैंक नोटों का मूल्य प्राप्त करना-इसलिए, ऐसे बैंक नोटों के धारक ऐसे अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं-भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 19 (एफ) और (जी) और 31 (2)।

उच्च मूल्य के बैंक नोट-विनिमय का समय और तरीका

एफ अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं माना गया-उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट ट्रस्ट द्वारा नकद के लिए दान टिकटों की घर-घर बिक्री-इस प्रक्रिया में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की प्राप्ति हाथ में रखी गई राशि दानदाताओं के नाम का खुलासा नहीं किया गया-कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया-राहत समिति द्वारा धन का संग्रह-उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी होने के तुरंत बाद संग्रह बक्से नहीं खोले गए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया-भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने ऐसे बैंक नोटों के आदान-प्रदान के दावे को अस्वीकार कर दिया क्योंकि दावेदार ऐसे बैंक नोटों के कब्जे को 16.1.1978 पर या उससे पहले साबित नहीं कर सके-आयोजितःभारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष थे-उनकी संतुष्टि

इस तरह के तथ्यों के आधार पर न्यायसंगत और उचित था और विकृत नहीं था-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था-भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 32।एच.

443

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1996] का समर्थन।4 एस सी आर।

444

प्रशासनिक कानूनः

क.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-ऑडी अल्टरम पार्टेम हाई डेनोमिना

बैंक नोट-विनिमय मूल्य का भुगतान-भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा इनकार-घोषणा प्रपत्रों को देर से जमा करने का कारण समझाने के लिए सुनवाई का पूर्व-निर्णयात्मक अवसर-दावेदार को नहीं दिया गया-हालांकि, ऐसे

दावेदार के आवेदन को खारिज करने से पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया अवसर-इस तरह की बर्खास्तगी के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी दिए गए विस्तृत कारण-यह मानते हुए भी आयोजित किया गया कि व्यक्तिगत सुनवाई का ऐसा अवसर था

प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य, दावेदार निर्णय के बाद की सुनवाई और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों को देखते हुए उस स्कोर पर कोई शिकायत नहीं उठा सका।

याचिकाकर्ता एक राहत समिति का अध्यक्ष था जो एक

मेडिकल डिस्पेंसरी।सोसायटी की कार्यकारी समिति ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ अस्पताल बनाने का निर्णय लिया।उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी समिति ने दान के माध्यम से धन एकत्र करने का निर्णय लिया और उसके लिए

डी.

प्रबंध के अनुसार एस और बी पर उद्देश्य दान बक्से रखे गए थे।

समिति के संकल्प में इन डिब्बों को समय-समय पर खोला जाता था।

सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति और

इस प्रकार एकत्र की गई राशि को अलग-अलग मिनट की किताबों में दर्ज किया गया था।

उच्च मूल्यवर्ग के बैंक की घोषणा के तुरंत बाद

ई.

नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978,16 जनवरी, 1978 को बी और एस दोनों में सोसायटी के पदाधिकारियों को कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं करने या किसी को भी किसी भी उच्च मूल्य के बैंक में जमा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए थे।

16 जनवरी, 1978 की मध्यरात्रि के बाद संग्रह बक्से में नोट।उस उद्देश्य के लिए एस और बी पर डिब्बों को सोसायटी द्वारा एफ को डिब्बों को खोलने के लिए कब्जे में ले लिया गया था।

}

एस में डिब्बों के संबंध में वे 20 जनवरी, 1978 को खोले गए थे और उनमें रुपये पाए गए थे।34,76,000 उच्च मूल्य के बैंक नोटों में।उपरोक्त राशि आवश्यक घोषणा के साथ जमा की गई थी

23 जनवरी, 1978 को बैंक में याचिकाकर्ता को एक पत्र के साथ समझाया गया

जी.

निर्धारित समय के भीतर इसे जमा करने में विफलता के लिए देरी।

याचिकाकर्ता-सोसायटी को बैंक के मुद्रा अधिकारी का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें एस में प्राप्त उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के उनके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सोसाइटी ने 445 के तुरंत बाद संग्रह बक्से खोलने में अपनी विफलता को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं था

जे. आर. शाह बनामआरबीआइ।

अध्यादेश जारी करना और यह कि यह उनके लिए स्थापित नहीं किया गया था-एक गुट कि नोट विमुद्रीकरण से पहले सोसायटी तक पहुंच गए थे।उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर सोसायटी ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 8 (3) के तहत केंद्र सरकार से अपील की।सोसायटी को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद केंद्र सरकार ने तर्कपूर्ण बी आदेश के साथ अपील को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता एक चैरिटी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के तहत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत था।

अधिनियम, 1950।याचिकाकर्ता-ट्रस्ट ने अस्पताल के प्रस्तावित सी निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने "अस्पताल भवन और उपकरण कोष" के लिए दान संग्रह अभियान शुरू किया।ट्रस्ट ने उस अभियान में भाग लेने के लिए भी सहमति व्यक्त की और तदनुसार फाउंडेशन के दान टिकटों की घर-घर जाकर नकद बिक्री की।याचिकाकर्ता-ट्रस्ट रुपये के टिकट बेचने में कामयाब रहा।1,57,050 जिसमें से रु.1,53,000 यह 153 रुपये के नोटों में थे।1,000 प्रत्येक।लेन-देन के तरीके को देखते हुए उन विभिन्न व्यक्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था जिन्हें दान टिकट वास्तव में बेचे गए थे।

16 जनवरी, 1978 को उच्च मूल्य के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश की घोषणा के परिणामस्वरूप ट्रस्ट ने रुपये के 153 मुद्रा नोटों के संबंध में एक घोषणा की।1,000 ई प्रत्येक, जिसे उन्होंने 19 जनवरी, 1978 को बैंक को टिकटों के साथ-साथ नोटों की बिक्री से प्राप्त किया था।उक्त घोषणा में उक्त मुद्रा नोटों का पूरा विवरण दिया गया था और विशेष रूप से यह भी कहा गया था कि राशि दान के रूप में प्राप्त की गई थी।ट्रस्ट ने अपने द्वारा बेचे गए टिकटों का पूरा विवरण देते हुए एक बयान भी प्रस्तुत किया, और अवलोकन के लिए टिकटों के काउंटर फॉयल प्रस्तुत किए।ट्रस्ट ने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि दान नकद में रह गया है और इसका उपयोग किया जाना बाकी है।हालांकि, बैंक ने उच्च मूल्य के बैंक नोटों के विनिमय मूल्य के भुगतान के लिए ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता-ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से अपील की जिसे खारिज कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता और उसके तहत पारित आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

च

जी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि विमुद्रीकरण।

राष्ट्र अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) और 31 का उल्लंघन किया; कि उत्तरदाताओं द्वारा उच्च मूल्य के नोटों को बदलने से इनकार करना सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] का समर्थन है।

4 एस सी आर।

446

संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए; कि ऐसा अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था; कि वे इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित थे; कि उच्च मूल्य के नोटों के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित समय अनुचित और अन्यायपूर्ण था; कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था; कि राशि को नकद में रखने का कोई कारण नहीं दिया गया था; कि उस पर कोई दायित्व नहीं डाला गया था।

विमुद्रीकरण अधिनियम के तहत दानदाताओं के नामों का खुलासा करने के लिए; और यह कि वे उत्तरदाताओं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं थे कि विचाराधीन नोट घोषणा से पहले या बाद में प्राप्त हुए थे।

विमुद्रीकरण अध्यादेश।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

एस.

अवधारित 1.1 .उच्च मूल्य के बैंक नोटों का प्रत्यक्ष प्रभाव

(विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 राज्य से उच्च मूल्य के बैंक नोटों के धारकों के कारण सार्वजनिक ऋण का सफाया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क कि उनकी संपत्ति अनिवार्य थी

अर्जित डी को स्वीकार करना होगा।यह देखना होगा कि क्या ऐसा अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था क्योंकि अनुच्छेद 31 (2) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के अलावा किसी भी संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था। प्रस्तावना से लेकर विमुद्रीकरण अधिनियम तक यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम को अघोषित धन के गंभीर खतरे से बचने के लिए पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल

ई ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन राज्य के राजकोष को अपने राजस्व की बड़ी मात्रा से भी वंचित कर दिया।उपरोक्त अधिनियम की बुराई को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (जी) पर आधारित याचिकाकर्ताओं के अन्य तर्क को अनिवार्य होने के बाद पूरी तरह से गलत समझा जाता है।

विवादित अधिनियम द्वारा उनकी संपत्ति का अधिग्रहण याचिकाकर्ताओं का अधिकार एफ समाप्त हो गया और इसके परिणामस्वरूप किसी अधिकार के प्रयोग या आनंद के लिए उचित प्रतिबंध का सवाल नहीं उठ सका, जो गैर-कानूनी हो गया। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क भी उतना ही असमर्थनीय है कि वे इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित थे, क्योंकि विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 उच्च मूल्य के बैंक नोटों के समान मूल्य के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया जी निर्धारित करती है।[454 - ई, 455-बी-डी]

एम. एम. पाठक बनामभारत संघ, [1978] 2 एस. सी. सी. 50, पर निर्भर था।1.2 .यह तर्क कि विमुद्रीकरण की धारा 7 और 8 के तहत उच्च एच मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित समय

.

447

जे. आर. शाह बनामआरबीआइ।

अधिनियम अनुचित था और याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला था, ए को धारा 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विमुद्रीकरण अधिनियम ने उच्च मूल्य के बैंक नोटों के प्रचलन को जल्द से जल्द रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया था।उच्च मूल्य के बैंक नोटों के 16.1.1978 की समाप्ति पर वैध निविदा होना बंद होने के परिणामस्वरूप और इसके हस्तांतरण में निषेध को देखते हुए

इसके बाद धारा 4 के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऐसे नोट रखने के लिए यह सुनिश्चित करना बिल्कुल आवश्यक था कि उच्च मूल्य के बैंक नोट धारकों को इसे दूसरों के कब्जे में स्थानांतरित करने का कोई अवसर उपलब्ध न हो।साथ ही इस तरह के नोटों के धारकों को इसे बदलने का उचित अवसर देना आवश्यक था।हालाँकि, यदि इस तरह के विनिमय का समय सी सीमित नहीं था, तो उच्च मूल्य के बैंक नोटों को वितरित किया जा सकता था और संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता था और ऐसा कोई भी हस्तांतरणकर्ता उसके बाद किसी भी दिन बैंक में जा सकता था और अपने नोटों को बदलने की मांग कर सकता था।उस स्थिति में बैंक के लिए यह साबित करना लगभग असंभव होता कि ऐसा व्यक्ति 16.1.1978 पर नोटों का मालिक या धारक नहीं था।ऐसी स्थिति में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विमुद्रीकरण अधिनियम का उद्देश्य ही क्या था

जो हासिल हुआ वह हार गया होगा।इन प्रतिस्पर्धी और हताश विचार के बीच संतुलन बनाने के लिए, धारा 7 (2)

विमुद्रीकरण अधिनियम ने नोटों को बदलने का समय 19.1.1978 तक सीमित कर दिया।धारा 7 और 8 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि धारा 7 (2) के अनुसार सभी विवरणों में पूर्ण घोषणा प्रस्तुत करने पर, धारक बिना किसी छूट या बाधा के बैंक से अपने नोटों का विनिमय मूल्य प्राप्त करने का हकदार था; इसके बाद, 24.1.1978 तक, वह बैंक से इस तरह के विनिमय का भी हकदार था यदि वह 19.1.1978 द्वारा आवेदन करने में अपनी असमर्थता के कारणों को संतोषजनक रूप से समझा सकता था और उस तारीख के बाद केंद्र सरकार को ऐसे विनिमय की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया था।उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में अधिनियम की ऐसी योजना होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस समय और तरीके से उच्च मूल्य के बैंक नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता था, वह अनुचित, अन्यायपूर्ण और

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।इसलिए विमुद्रीकरण अधिनियम जी विधान का एक वैध हिस्सा है। [455 - ई-एच; 456-ए-एफ]

2. यह मानते हुए कि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य था, याचिकाकर्ता कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकते।अपीलीय प्राधिकरण के लिए उस स्कोर पर शिकायत ने उन्हें इस तरह का एच 448 दिया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. उनकी अपील को खारिज करने से पहले एक अवसर। अपीलीय प्राधिकरण ने समय पर घोषणा दाखिल नहीं करने के लिए सोसायटी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में असमर्थता के विस्तृत कारण भी दिए हैं।विमुद्रीकरण अधिनियम के तहत यदि उच्च मूल्य के बैंक नोटों के धारक ने उन नोटों को 16.1.1978 के बाद प्राप्त कर लिया होता तो वह उन्हें बदलने का हकदार नहीं होता।यदि, इसलिए, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को संतोष प्राप्त हुआ कि

सोसायटी यह साबित करने में विफल रही कि उच्च मूल्य के बैंक नोट, जिनके लिए मूल्य का दावा किया गया था, उसके हाथों में या उससे पहले पहुँच गए थे, 16.1.1978 भुगतान को वैध रूप से अस्वीकार किया जा सकता था।भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्र सरकार के निष्कर्ष तथ्यों के थे और इस न्यायालय के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया था जिससे यह संकेत मिले कि विवादित आदेश विकृत थे।दूसरी ओर, अभिलेख पर सी सामग्री के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि जिन कारणों का वजन किया गया है

अधिकारियों द्वारा अपने उच्च मूल्य के बैंक नोटों के बदले में सोसायटी को भुगतान करने से इनकार करना ठोस और आश्वस्त करने वाला था।[459 - डी-ई, 460-सी]3. विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत राशि को नकद में रखने के कारणों और दानदाताओं के नामों का खुलासा किया जाना है।

डी.

विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विवरणों के प्रकटीकरण के कारणों की तलाश करना दूर की बात नहीं है।उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के वैध निविदा नहीं होने के बाद 16.1.1978 की अवधि समाप्त होने पर उन्हें दूसरों के कब्जे में स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन नोटों को बदलने का अधिकार और अवसर केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जिनके पास 16.1.1978 पर वही था।इसलिए, यह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कि घोषणाकर्ता के पास आई. डी. 1 पर या उससे पहले नोट थे, बैंक को आवश्यक जांच करने की आवश्यकता थी और उस संदर्भ में विवरणों का पूर्ण प्रकटीकरण बिल्कुल आवश्यक था।न्यास द्वारा प्रस्तुत विवरणों को संबंधित अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला

च

क्योंकि अधिकारियों के अनुसार, ट्रस्ट के पास एक बैंक खाता था और निकट भविष्य में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह बहुत असामान्य लग रहा था कि इसे उपयोग के लिए हाथ में रखा जाएगा।जहाँ तक दानदाताओं के नाम का खुलासा करने में ट्रस्ट की विफलता का संबंध है, टिप्पणी यह थी कि यह एक अस्पष्ट उत्तर था और यह स्थापित नहीं करता था कि क्या नोट थे।

जी अध्यादेश से पहले या बाद में प्राप्त किया गया।इसके अलावा, यह देखा गया कि चूंकि राशि दानदाताओं से एकत्र की गई थी, इसलिए यह कारण नहीं था कि सभी दानदाता गुमनाम रहना चाहेंगे, हालांकि उन्होंने एक अच्छे कारण के लिए दान किया था।भुगतान से इनकार करने में इस तरह से प्रचार किए गए आधार

याचिकाकर्ताओं को अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है ताकि इस उच्च न्यायालय को इसमें बाधा डालने का अधिकार मिल सके।[462 - एफ-एच, 463-ए-सी] जे. आर. शाह बनाम।

आरबीआइ। (एम. के. मुखर्जी, जे.) 449 मूल न्यायनिर्णयः1979 ए की रिट याचिका (सी) संख्या 1188

आदि।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) याचिकाकर्ताओं के लिए कृष्ण महाजन और पी. एच. पारेख।

उत्तरदाताओं के लिए एच. एन. साल्वे, सुश्री ए. सुभाषिनी एन. पी., के. एस. परिहार और एच. एस. परिहार।

उत्तरदाता संख्या 3 के लिए डॉ. आर. आर. मिश्रा और सुश्री बीनू टम्टा

एस.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. के. मुखर्जी, जे. उच्च न्यायालय की संवैधानिक वैधता

मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 (इसके बाद)

'विमुद्रीकरण अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और कुछ आदेशों की वैधता।भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन याचिकाओं में इसके तहत पारित याचिकाओं को चुनौती दी गई है।इस अधिनियम ने एक समान शीर्षक वाले अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और जो 16 जनवरी, 1978 को लागू हुआ था। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, इस स्तर पर न केवल विमुद्रीकरण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (संक्षेप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम) का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (संक्षेप में बैंक) को बैंक नोट जारी करने का अधिकार देता है और उन नोटों को बदलने के लिए उस पर एक दायित्व लगाता है।

डी.

बैंक के मुद्दे को विनियमित करने के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत बैंक का गठन किया गया है।भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने और आम तौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट एफ प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करने की दृष्टि से नोटों और भंडारों को रखना।उस अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि बैंक को बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा।धारा 24, जो नोटों के मूल्य को निर्धारित करती है, निम्नानुसार हैः

" (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बैंक नोट जी

दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये या ऐसे अन्य मूल्यवर्ग राष्ट्रीय मूल्यों के हों, जो केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर दस हजार रुपये से अधिक न हों।

इस संबंध में निर्दिष्ट करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] एस. यू. पी.4 एस सी आर।

450

(2) केंद्र सरकार, की सिफारिश पर

क.

केंद्रीय बोर्ड, ऐसे मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी न करने या जारी न करने का निर्देश देता है जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है

इस ओर से "।

धारा 26 में कहा गया है कि प्रत्येक बैंक नोट वैध होगा।

भारत में किसी स्थान पर भुगतान में या उसमें व्यक्त राशि के कारण और केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।इसमें आगे कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार हालांकि भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है

कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से किसी भी मूल्य के सी बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला बैंक के ऐसे कार्यालय या एजेंसी को छोड़कर और उस हद तक कानूनी निविदा नहीं रहेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।आर. बी. आई. अधिनियम की दूसरी धारा हमारे लिए प्रासंगिक है

उद्देश्य धारा 39 है जो भारत सरकार के बैंक नोटों और मुद्रा नोटों के बदले में मांग पर रुपये के सिक्के या कम मूल्य के नोट जारी करने के लिए बैंक पर एक स्पष्ट दायित्व लगाती है।

डी.

1

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि बैंक एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है और जब मांग की जाती है तो उन नोटों को बदलने का दायित्व रखता है, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार द्वारा उसे उस दायित्व से कब और उस हद तक मुक्त किया जाता है।

ई.

अब विमुद्रीकरण अधिनियम पर आते हुए हम सबसे पहले पाते हैं कि

धारा 2 (डी) में 'मूल्यवर्ग के बैंक नोट' को रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये के मूल्यवर्ग के बैंक नोट के रूप में परिभाषित किया गया है।धारा 3 घोषणा करती है कि 16 जनवरी, 1978 की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 में कुछ भी निहित होने के बावजूद सभी उच्च मूल्य के बैंक नोट भुगतान में या किसी भी स्थान पर खाते में वैध मुद्रा नहीं होंगे।धारा 4 जो उच्च मूल्य के बैंक नोटों के हस्तांतरण और प्राप्ति को प्रतिबंधित करती है, निम्नानुसार हैः

च

" इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति,

जी.

16 जनवरी, 1978 की तारीख, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तांतरण या किसी अन्य व्यक्ति से उसके कब्जे में कोई उच्च राशि प्राप्त करना।

मूल्यवर्ग का बैंक नोट "।

विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8, जिसके इर्द-गिर्द याचिकाकर्ताओं की दलीलों का एक बड़ा हिस्सा घूमता है, निम्नानुसार हैः

जे. आर. शाह बनामआरबीआइ। [एम. के. मुखर्जी, जे.] 451

" धारा 7.अन्य व्यक्तियों द्वारा रखे गए उच्च मूल्य के बैंक नोटों का आदान-प्रदानः

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, बैंक या सरकारी कोषागार बी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी उच्च मूल्य के बैंक नोट का आदान-प्रदान 16 जनवरी, 1978 के बाद केवल नोट के निविदा पर किया जा सकता है -

(क) जहाँ उच्च मूल्य के बैंक नोट का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास है, स्वयं व्यक्ति के पास है; या जहाँ व्यक्ति भारत से अनुपस्थित है, संबंधित व्यक्ति या किसी व्यक्ति के पास है।

एस.

जहाँ व्यक्ति अपने कार्यों में भाग लेने के लिए मानसिक रूप से अक्षम है, अपने अभिभावक द्वारा या अपनी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ख) से (च)

डी.

और इस धारा में दिए गए समय के भीतर और तरीके से।(2) इस धारा के तहत एक उच्च मूल्य के बैंक नोट को बदलने के लिए निविदा देने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की तीन प्रतियां उस प्रपत्र द्वारा आवश्यक विवरणों को पूरा करते हुए तैयार करेगा और 19 जनवरी, 1978 के बाद, ऐसी प्रतियां उस उच्च मूल्य के बैंक नोट के साथ व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा जो वह चाहता है।

विनिमय -

((a) से (c)

च

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर रहता है जो उसके भीतर नहीं है

ऐसे किसी भी कार्यालय या शाखा की सुविधाजनक पहुंच, या यदि, उम्र, दुर्बलता या बीमारी के कारण वह वहां उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह जी बीमित डाक द्वारा उसके संबंध में घोषणा की तीन प्रतियों के साथ उच्च मूल्य के बैंक नोटों को 19 जनवरी, 1978 के बाद बॉम्बे में रिजर्व बैंक को भेज सकता है।

(3)

(4) जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि घोषणा पूर्ण एच. सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1996] एस. पी. पी. नहीं है।

4 एस सी आर।

452

सभी सामग्री विवरणों में, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या

क.

सी. एल. के तहत अधिसूचित कोई भी बैंक।(ग) यथास्थिति, उप-धारा (2), जिसके लिए उच्च मूल्यवर्ग के विनिमय के लिए आवेदन

इस धारा के तहत बनाए गए बैंक नोट, उक्त नोटों के विनिमय मूल्य का भुगतान ठीक से शुरू किए गए खाते में जमा करने के लिए करेंगे।

मालिक या उद्घोषक, जैसा भी मामला हो, किसी भी अनुसूचित के साथ

बैंक।

बशर्ते कि यदि, जैसा भी मामला हो, मालिक या घोषणाकर्ता का बैंक खाता नहीं है, तो उक्त नोटों के विनिमय मूल्य का भुगतान केवल उचित पहचान पर और जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक किया जाएगा।

एस.

यदि ऐसा किया जाता है, तो राशि रिजर्व बैंक या बैंक, जैसा भी मामला हो, की अभिरक्षा में रहेगी, जिसे उच्च मूल्य के बैंक नोटों की निविदा दी गई थी।

(5) जहां यह प्रतीत होता है कि घोषणा सभी सामग्री विवरणों में पूरी नहीं की गई है, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या

डी.

अधिसूचित बैंक, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए उपरोक्त आवेदन किया गया है, जब तक कि घोषणाकर्ता बिना किसी देरी के चूक की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, उस बैंक नोट को स्वीकार करने और भुगतान करने से इनकार कर देगा जिससे

घोषणा संबंधित है, और जहां वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो घोषणा की एक प्रति घोषणा करने वाले को दर्ज करने के बाद वापस कर देगा।

ई.

उस तारीख को जिस दिन इसे प्रस्तुत किया जाता है और वह मामला केंद्र सरकार को भेजेगा, जिस पर वह घोषणा की एक प्रति भेजेगा, जिसमें इनकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण होगा।

बैंक नोटों के लिए भुगतान करें।

(6) केंद्र सरकार को किसी भी निर्दिष्ट घोषणा की आवश्यकता हो सकती है

च

उप-धारा (5) में अपनी घोषणा को उस हद तक और ऐसे विवरणों के संबंध में प्रवर्धित करने के लिए जो वह उचित समझे और जब तक कि घोषणाकर्ता ऐसी आवश्यकता का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम न हो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान की धारा से इनकार कर सकता है जिससे घोषणा संबंधित है।

जी.

(7) केंद्र सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा और उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में उस अवधि को बढ़ा सकता है जिसके दौरान उच्च मूल्य के बैंक नोटों के लिए निविदा दी जा सकती है।

इस धारा के तहत विनिमय।

एच. जे. आर. शाह बनामआर. बी. आई. एम. के. मुखर्जी, जे.]

453

धारा 8.- धारा 7 में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद नोटों का आदान-प्रदान।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उच्च मूल्य के बैंक नोट के आदान-प्रदान के लिए आवेदन करने में विफल रहता है।

•

उस धारा में दिया गया समय उस धारा के तहत आवश्यक घोषणा के साथ नोटों को उप-धारा (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर रिजर्व बैंक को भेज सकता है।

उस धारा का, 24 जनवरी, 1976 के बाद नहीं, आवेदन करने में उनकी विफलता के कारणों को समझाते हुए एक बयान के साथ

1 .

उक्त समय सीमा के भीतरः

एस.

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर रहता है जो उसके भीतर नहीं है

उक्त स्थानों में से किसी पर भी रिजर्व बैंक के उप-कार्यालय, कार्यालय या शाखा तक सुविधाजनक पहुँच या यदि, आयु, दुर्बलता या बीमारी के कारण, वह वहां उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह धारा 7 में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने

में अपनी विफलता के कारणों को समझाते हुए एक विवरण के साथ बीमित डाक द्वारा धारा 7 के तहत आवश्यक घोषणा की तीन प्रतियों के साथ उच्च मूल्य के बैंक नोटों को बॉम्बे में रिजर्व बैंक को भेज सकता है।

(2) रिजर्व बैंक, यदि ऐसी पूछताछ ई करने के बाद संतुष्ट हो जाता है जो वह आवश्यक समझता है कि धारा 7 में दिए गए समय के भीतर नोटों को विनिमय के लिए जमा करने में विफलता के कारण वास्तविक हैं, तो उस धारा की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट तरीके से नोटों के मूल्य का भुगतान कर सकता है।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा उप-धारा (2) के तहत नोटों के मूल्य का भुगतान करने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे इस तरह के इनकार के संचार के चौदह दिनों के भीतर केंद्र सरकार को अपील कर सकता है।

विमुद्रीकरण अधिनियम पर हमला करते हुए जी की ओर से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आर में निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 (निरस्त होने के बाद से), जो उनके लिए भौतिक समय पर उपलब्ध थे।उनके तर्क को विस्तार से बताते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 बैंक पर यह दायित्व डालती है कि वह जब भी उच्च मूल्य के बैंक नोटों का भुगतान करे

निविदा दी गई और केंद्र सरकार ने इस तरह के भुगतान की गारंटी दी लेकिन एच सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1996] एसयूपीपी पर।

4 एस सी आर।

454

आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 3 को ध्यान में रखते हुए, एक उद्घोषणा या विवादित अधिनियम के तहत उन नोटों का कानूनी रूप से चलन समाप्त हो गया और इसके परिणामस्वरूप, बैंक और उस मामले के लिए केंद्रीय सरकार अपने ऐसे दायित्वों से मुक्त हो गई।दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विवादित अधिनियम ने उच्च मूल्य के बैंक नोटों के धारकों को बैंक से देय और देय ऋण को समाप्त कर दिया।द.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के ऋणों को समाप्त करना संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अर्थ के भीतर संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है और चूंकि अधिग्रहण जनता के लिए नहीं किया गया था।

उद्देश्य और न ही इसके संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए विवादित अधिनियम में पर्याप्त और उचित प्रावधान शामिल किए गए थे, आई. एम. सी. प्रस्तावित अधिनियम उपरोक्त अनुच्छेद का उल्लंघन था।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें उच्च मूल्य के बैंक नोटों को प्राप्त करने और रखने और विमुद्रीकरण अधिनियम में जहां तक इसका प्रावधान है, उनका उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार है।

उच्च मूल्य के बैंक नोटों के विनिमय मूल्य का भुगतान न करना, सिवाय इसके कि

एस.

धारा 7 और 8 में जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, वे अनुचित हैं।

डी.

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) के तहत उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध।

चूँकि यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि उच्च का प्रत्यक्ष प्रभाव

मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 राज्य से उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट धारकों के कारण सार्वजनिक ऋण से ई को समाप्त करने वाला अध्यादेश है, याचिकाकर्ताओं का दूसरा तर्क कि उनकी 'संपत्ति' अनिवार्य रूप से अर्जित की गई थी, इस न्यायालय के एम. एम. पाठक बनाम संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए।संघ का

भारत, [1978] 2 एस. सी. सी. 50, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 31 के अनुच्छेद 19 (1) (च) और खंड (2) के अर्थ के भीतर 'संपत्ति' में प्रत्येक

•

च

संपत्ति का रूप, मूर्त या अमूर्त, जिसमें ऋण और कार्रवाई में विकल्प शामिल हैं और राज्य से देय और देय सार्वजनिक ऋण का उन्मूलन ऐसे 'ऋण' का अनिवार्य अधिग्रहण है।

अगला सवाल जो अनिवार्य रूप से निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या ऐसा अधिग्रहण अनुच्छेद 31 (2) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के अलावा किसी भी संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था।इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम विमुद्रीकरण अधिनियम की प्रस्तावना पर लाभदायक नज़र डाल सकते हैं जो इस प्रकार हैः

" जबकि उच्च मूल्य के बैंक नोटों की उपलब्धता

एच.

सी. जे. आर. शाह बनामआरबीआइ। (एम. के. मुखर्जी, जे.) 455

लेन-देन ए के वित्तपोषण के लिए धन के अवैध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं या जो अवैध उद्देश्यों के लिए हैं और इसलिए सार्वजनिक हित में उच्च मूल्य के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम बी को अघोषित धन के गंभीर खतरे से बचने के लिए पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल देश की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, बल्कि राज्य के राजकोष को उसके राजस्व की बड़ी मात्रा से भी वंचित कर दिया था।उपरोक्त अधिनियम की बुराई को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।संविधान के 19 (1) (च) और (छ) के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अन्य तर्क को पूरी तरह से गलत समझा जाता है क्योंकि विवादित अधिनियम द्वारा उनकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बाद याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार दिया गया है

समाप्त हो गया और परिणामस्वरूप किसी अधिकार के प्रयोग या आनंद के लिए उचित प्रतिबंध का सवाल, जो गैर-स्थायी हो गया, उत्पन्न नहीं हो सका, याचिकाकर्ताओं का तर्क समान रूप से असमर्थनीय है कि वे थे

इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित, क्योंकि विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 उच्च मूल्य के बैंक नोटों के लिए डी को लागू करने और उसके तहत निर्धारित तरीके से समान मूल्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भले ही यह माना गया हो कि अनुच्छेद 31 का उल्लंघन निर्धारित समय के लिए नहीं किया गया था।

विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत उच्च मूल्य के बैंक नोटों का आदान-प्रदान अनुचित था और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।जब अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर उस उद्देश्य के संदर्भ में विचार किया जाता है जिसे विमुद्रीकरण अधिनियम प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात्, उच्च मूल्य के बैंक नोटों के संचलन को जल्द से जल्द रोकने के लिए, याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।16 जनवरी, 1978 की समाप्ति पर उच्च मूल्य के बैंक नोटों का वैध चलन समाप्त होने पर और उसके बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऐसे नोटों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध को देखते हुए, जैसा कि धारा 4 के तहत परिकल्पित किया गया था, यह सुनिश्चित करना बिल्कुल आवश्यक था कि उच्च मूल्य के बैंक नोट 'जी' के धारकों को इसे दूसरों के कब्जे में स्थानांतरित करने का कोई अवसर उपलब्ध न हो।साथ ही ऐसे नोटों के धारकों को उनका आदान-प्रदान करने का उचित अवसर देना भी आवश्यक था।हालाँकि, यदि इस तरह के विनिमय का समय सीमित नहीं था, तो उच्च मूल्य के बैंक नोटों को वितरित किया जा सकता था और संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता था और ऐसा कोई भी हस्तांतरणकर्ता किसी भी दिन एच 456 पर बैंक में जा सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] एस. यू. पी.4 इसके बाद एस. सी. आर. ए. अपने नोटों के आदान-प्रदान की मांग करता है।उस स्थिति में बैंक के लिए यह साबित करना लगभग असंभव होता कि ऐसा व्यक्ति 16 जनवरी, 1978 को नोटों का मालिक या धारक था।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी स्थिति में विमुद्रीकरण अधिनियम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता था, वह विफल हो जाता।जाहिर है, इन प्रतिस्पर्धी और अलग-अलग विचारों के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 7 (2)

विमुद्रीकरण अधिनियम ने 19 जनवरी, 1978 तक नोटों को बदलने का समय सीमित कर दिया।हालाँकि, इसके बाद भी, धारा 8 को देखते हुए, उच्च मूल्य के बैंक नोटों को 24 जनवरी, 1978 तक बैंक से बदला जा सकता था, बशर्ते कि निविदाकर्ता विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा सी 7 (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर इस तरह के विनिमय के लिए आवेदन करने में अपनी विफलता के कारणों को समझाने में सक्षम हो।बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, धारा 7 की उप-धारा (7) में प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को कारण दर्ज करने की अनुमति दी गई है।

लेखन, किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में उस अवधि को बढ़ाने के लिए जिसके दौरान उच्च मूल्य के बैंक नोटों को विनिमय के लिए निविदा दी जा सकती है।एक संयुक्त से

डी.

धारा 7 और 8 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि

19 जनवरी, 1978 तक धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार सभी विवरणों में पूर्ण घोषणा, धारक बिना किसी छूट या बाधा के बैंक से अपने नोटों का विनिमय मूल्य प्राप्त करने का हकदार था; इसके बाद, 24 जनवरी, 1978 तक, वह बैंक ई से इस तरह के विनिमय का भी हकदार था, यदि वह बैंक ई द्वारा आवेदन करने में अपनी असमर्थता के कारणों को संतोषजनक रूप से समझा सकता था।

19 जनवरी, 1978 और उस तारीख के बाद जब केंद्र सरकार को इस तरह के विनिमय की अवधि बढ़ाने का अधिकार था। उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में अधिनियम की ऐसी योजना होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस समय और तरीके से उच्च मूल्य के बैंक नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता था, वह अनुचित, अन्यायपूर्ण और नियमों का उल्लंघन था।

च

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार।अब जब हमने विमुद्रीकरण अधिनियम को एक वैध कानून पाया है, तो हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिट याचिकाओं के संबंधित याचिकाकर्ताओं के उच्च मूल्य के बैंक नोटों को बदलने से इनकार करना उचित है या नहीं।

याचिका सं. लिखें।1188 1979 का

याचिकाकर्ता राहत सोसायटी का अध्यक्ष है जो जे. आर. एसएचएएच बनाम चलाता है।

एच.

आरबीआइ। [एम. के. मुखर्जी, जे.] 457

सूरत में मेडिकल डिस्पेंसरी।वर्ष 1974 में ए द सोसाइटी की कार्यकारी समिति ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ अस्पताल बनाने का निर्णय लिया।उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी समिति ने दान के माध्यम से धन एकत्र करने का निर्णय लिया और उस उद्देश्य के लिए सूरत और बॉम्बे में दान बक्से रखे गए।4 अगस्त, 1974 के प्रबंध समिति के प्रस्ताव के अनुसार इन डिब्बों को समय-समय पर सोसायटी के बी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में खोला जाता था और इस तरह एकत्र की गई राशि

इन्हें अलग-अलग सूक्ष्म पुस्तकों में दर्ज किया गया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्च मूल्य के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 की घोषणा के तुरंत बाद,

16 जनवरी, 1978 को बॉम्बे और सूरत दोनों में सोसायटी सी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई भी जमा राशि स्वीकार न करें या किसी को भी बाद में संग्रह बक्से में कोई भी उच्च मूल्य के बैंक नोट जमा करने की अनुमति दें।

16 जनवरी, 1978 की मध्यरात्रि।उस उद्देश्य के लिए सूरत और बॉम्बे के डिब्बों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और सोसायटी द्वारा डिब्बों को खोलने के लिए कदम उठाए गए।डी बॉम्बे में संग्रह बक्से, जो 17 जनवरी, 1978 की दोपहर को खोले गए थे, थे

रुपये पाए गए।22,11,000 उच्च मूल्य के बैंक नोटों में।इस प्रकार प्राप्त राशि को मिनट बुक में ठीक से छोटा किया गया था और कैश बुक में दर्ज किया गया था।इसके बाद सोसायटी ने उन नोटों के आदान-प्रदान के लिए प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक वैधानिक घोषणा पत्र प्राप्त किया और घोषणा के साथ 19 जनवरी, 1978 को भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे ई को नोट वितरित किए।

सूरत के डिब्बों के संबंध में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वे थे

20 जनवरी, 1978 को खोला गया और इसमें रु।34,76,000 उच्च मूल्य के बैंक नोटों में।उपरोक्त राशि को आवश्यक एफ घोषणा के साथ याचिकाकर्ता द्वारा 23 जनवरी, 1978 को बॉम्बे में बैंक में एक पत्र के साथ जमा किया गया था, जिसमें निर्धारित समय के भीतर इसे जमा करने में विफलता के लिए देरी की व्याख्या की गई थी।

इसके बाद समय-समय पर सोसायटी ने पत्रों को संबोधित किया और भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे ने जमा किए गए उच्च मूल्य के बैंक नोटों के मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा।लेकिन उसे तब तक कुछ नहीं मिला था।

25 अप्रैल, 1978, जब सोसायटी को बैंक के मुद्रा अधिकारी का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें सूरत में प्राप्त उच्च मूल्य के बैंक नोटों के आदान-प्रदान के उनके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सोसाइटी ने तुरंत संग्रह बक्से खोलने में अपनी विफलता को संतोषजनक रूप से नहीं बताया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. ए. ने अध्यादेश जारी करने के बाद कहा कि यह उनके लिए संतोषजनक नहीं था कि नोट विमुद्रीकरण से पहले सोसायटी तक पहुंच गए थे।उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर सोसायटी ने इसके तहत अपील की

केंद्र सरकार को विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 8 (3)।सोसायटी को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद केंद्र सरकार ने निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ अपील को खारिज कर दियाः

" जहां तक सूरत में पाए गए नोटों का संबंध है, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से सहमत है कि अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद सूरत में संग्रह बक्से खोलने में ट्रस्ट की विफलता को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है।न्यासियों ने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी स्वीकार की है

एस.

16 जनवरी, 1978 की शाम को अध्यादेश जारी किया गया और 17 जनवरी को बॉम्बे में डिब्बे खोले गए।वे इसी तरह की सावधानी बरत सकते थे और सूरत के डिब्बों को भी तुरंत खोल सकते थे।तथ्य यह है कि बक्से 20 जनवरी, 1978 को खोले गए थे और फिर 23 जनवरी, 1978 को घोषित किए गए थे।

डी.

इस बारे में संदेह की गुंजाइश छोड़ दें कि क्या ट्रस्ट के पास 16 जनवरी, 1978 को या उससे पहले उच्च मूल्य के नोट थे

और बाद में नहीं।

ट्रस्ट ने संग्रह का विवरण भी प्रस्तुत किया है

पहले के अवसरों पर बक्से।1977 के दौरान डिब्बों को खोला गया था।

ई.

पाँच अवसर, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

सूरत में नकद बक्से के संग्रह का विवरण।

1977

राशि

च

रु.18,012

जनवरी

रु.16,161

अप्रैल

रु.56,000

मई

रु.10,000

जून

रु.20,051

11 नवंबर

जी.

इससे पहले के अवसरों पर यह राशि बहुत कम थी और 11 नवंबर, 1977 को यह केवल रु।20,051 .इस प्रकार 5 महीनों से अधिक समय में, 77 जून से 77 नवंबर तक, कुल संग्रह रु।20,000 जो औसतन लगभग रु।5,000 प्रति माह।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सबसे अधिक संभावना नहीं लगती है कि

459

एच. जे. आर. शाह बनामआर. बी. आई. एम. के. मुखर्जी, जे.]

अगले दो महीनों यानी नवंबर, 1977 से 16 जनवरी, 1978 तक कुल दान रु।34,75,519 जिसमें से रु.34,76,000 यह उच्च मूल्य के नोटों में होगा।इसके अलावा अपीलकर्ता यह भी साबित नहीं कर पाया था कि अतीत में भी ट्रस्ट को चैरिटी बॉक्स से उच्च मूल्य के नोटों में दान मिल रहा था और यह एक नियमित सुविधा थी।

बी बैंक के मुद्रा अधिकारी के आदेश को लागू करने में यह था

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि सोसायटी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था ताकि वह घोषणा पत्र जमा करने में देरी के कारणों को समझा सके।भले ही हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सुनवाई का ऐसा अवसर सी के प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य था, याचिकाकर्ता उस स्कोर पर कोई शिकायत नहीं उठा सकता है क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण ने उनकी अपील को खारिज करने से पहले उन्हें ऐसा अवसर दिया था।इसके अलावा, जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलीय प्राधिकरण ने समय पर घोषणा दाखिल नहीं करने के लिए सोसायटी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में असमर्थता के लिए विस्तृत कारण दिए हैं।इसके तहत

डी.

विमुद्रीकरण अधिनियम यदि उच्च मूल्य के बैंक नोटों के धारक ने 16 जनवरी, 1978 के बाद उन नोटों को प्राप्त कर लिया होता तो वह उन्हें बदलने का हकदार नहीं होता।यदि, इसलिए, बैंक और केंद्र सरकार को यह संतोष प्राप्त होता है कि सोसायटी यह साबित करने में विफल रही कि उच्च मूल्य के बैंक नोट, जिनके लिए मूल्य का दावा किया गया था, 16 जनवरी, 1978 को या उससे पहले उसके हाथों में पहुंच गए थे, तो भुगतान को वैध रूप से अस्वीकार किया जा सकता है।ई हालांकि यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाताओं को बॉम्बे के संग्रह बक्से में पाए गए नोटों के संबंध में विनिमय के अपने दावे को स्वीकार करने के बाद सूरत में प्राप्त नोटों के संबंध में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करना चाहिए था।ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया था, जिसने निम्नलिखित आक्षेपों के साथ इसे खारिज कर दियाः

" भारत सरकार ने मामले के सभी तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उनका मानना है कि बॉम्बे में 17 तारीख को खोले गए और 19 तारीख को घोषित किए गए चैरिटी बॉक्स में पाई गई राशि के बारे में निर्णय सूरत में चैरिटी बॉक्स में पाए गए नोटों पर लिए गए निर्णय के लिए शायद ही कोई प्रासंगिक है।बॉम्बे में दान बक्से में पाए गए नोटों के बारे में घोषणा निर्धारित समय यानी 19 जनवरी, 1978 के भीतर थी और यदि प्रपत्र सभी सामग्री विवरणों में पूर्ण थे तो बैंक के पास एच नोटों को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

जी 460

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1996] एस. यू. पी.4 एस. सी. आर. ए. कानून के प्रावधानों के अनुसार।हालांकि, 19 तारीख के बाद 24 तारीख तक दायर किए गए घोषणा राशन के लिए घोषणाकर्ता को देरी के कारणों के बारे में रिजर्व बैंक को संतुष्ट करना था और केवल तभी जब रिजर्व बैंक पूरी तरह से संतुष्ट हो तो नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि बॉम्बे में बक्से में पाए गए नोट और सूरत में पाए गए नोट एक अलग आधार पर खड़े हैं।

हालाँकि, हमें इस मामले में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यों के हैं और यह इंगित करने के लिए हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया है कि विवादित आदेश विकृत हैं।वास्तव में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री हमें यह मानने के लिए राजी करती है कि सी को उनके उच्च मूल्य के बैंक नोटों के बदले में सोसायटी को भुगतान करने से इनकार करने के लिए अधिकारियों के साथ वजन करने वाले कारण ठोस और आश्वस्त करने वाले हैं।इसलिए, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

1

याचिका सं. लिखें।97-100 1981 का

डी.

याचिकाकर्ता तुलसीराम मानसादेवी के न्यासी हैं।

चैरिटी ट्रस्ट (संक्षिप्त में 'ट्रस्ट') जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।ट्रस्ट का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, गरीबों और बेसहारा लोगों को सहायता प्रदान करना है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कभी-कभी 1977 में एक गोपालदास अग्रवाल फाउंडेशन।ई (संक्षेप में 'फाउंडेशन') ट्रस्ट के साथ सामान्य न्यासियों वाले एक ट्रस्ट ने अस्पताल के प्रस्तावित निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने 'अस्पताल भवन और उपकरण कोष' के लिए दान संग्रह अभियान शुरू किया।ट्रस्ट ने उस अभियान में भाग लेने के लिए भी सहमति व्यक्त की और तदनुसार फाउंडेशन के दान टिकटों की घर-घर नकद में बिक्री शुरू की।एफ उस उद्देश्य के लिए, ट्रस्ट को रुपये के दान टिकट प्राप्त हुए।3,00,000 फाउंडेशन से और 15 नवंबर, 1977 और 14 जनवरी, 1978 के बीच की अवधि के दौरान रु।1,57,050 जिसमें से रु.1,53,000 यह 153 रुपये के नोटों में थे।1,000 प्रत्येक।उपरोक्त बिक्री न्यास के कर्मचारियों, इसके प्रतिनिधियों और न्यासियों से जुड़े या उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों के माध्यम से प्रभावित हुई, जिन्होंने ऐसी बिक्री का विस्तृत जी लेखा प्रस्तुत किया।बिक्री के संबंध में प्राप्तियां दर्ज की गईं

टी

न्यास की नकद पुस्तिका प्राप्त होने पर उसे उक्त प्रतिष्ठान को सौंप दिया गया।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, लेन-देन के तरीके को देखते हुए न तो कोई रिकॉर्ड रखा गया था और न ही उन विभिन्न व्यक्तियों का रखा जा सकता था जिन्हें दान टिकट वास्तव में बेचे गए थे।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का मानना है कि दान जे. आर. शाह बनाम में प्राप्त किया गया था।

आरबीआइ। [एम. के. मुखर्जी, जे. जे. 461

कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सहयोगियों से नकद और ए में रखे गए फॉर्म को उसी रूप में सीधे फाउंडेशन को सौंपना था, जिसकी ओर से राशि एकत्र की गई थी।

उच्च मूल्यवर्ग के बैंक की घोषणा के बाद परिणाम

16 जनवरी, 1978 को नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश ट्रस्ट ने रुपये के 153 नोटों के संबंध में एक घोषणा की।1,000 प्रत्येक, जो उन्हें टिकटों की बिक्री के साथ-साथ 19 जनवरी, 1978 को बैंक को बॉम्बे में उसके कार्यालय में नोटों के साथ प्राप्त हुआ था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार उक्त घोषणा में उक्त मुद्रा नोटों का पूरा विवरण दिया गया था और यह भी विशेष रूप से कहा गया था कि राशि दान के रूप में प्राप्त की गई थी।4 अक्टूबर, 1978 के अपने पत्र द्वारा, बैंक ने हालांकि ट्रस्ट से निम्नलिखित अधिक विवरणों के लिए सी की मांग कीः

(क) दान संग्रह के लिए जारी किए गए टिकटों और वास्तव में 14 जनवरी, 1978 तक बेचे गए टिकटों का सांप्रदायिक विवरण; (ख) क्या उच्च मूल्य के नोट सीधे प्राप्त हुए थे, और (घ) यदि नहीं, तो कब और किससे बदले गए थे, और उक्त न्यास से यह भी पूछा -

(ग) अवलोकन और वापसी के लिए टिकटों के काउंटर-फॉइल प्रस्तुत करना; उक्त अनुरोधों के जवाब में ट्रस्ट ने ई द्वारा बेचे गए टिकटों का पूरा विवरण देते हुए एक बयान प्रस्तुत किया, और अवलोकन के लिए टिकटों के काउंटर फॉइल प्रस्तुत किए।

इसके बाद 16 अगस्त, 1979 के अपने पत्र द्वारा बैंक ने न्यास को सूचित किया कि न्यास द्वारा दायर घोषणा को इस रूप में नहीं माना जा सकता है

च

निम्नलिखित कारणों से सभी सामग्री विवरणों में पूर्णः(क) उक्त घोषणा प्रपत्र के कॉलम 15 के खिलाफ, यह कहा गया है कि "दान के रूप में प्राप्त राशि हाथ में लंबित है।

उसी का उपयोग "।यह बहुत असामान्य लगता है क्योंकि उक्त न्यास का एक बैंक खाता था और निकट भविष्य में जी का उपयोग करने के लिए नकदी की आवश्यकता नहीं थी और

(ख) घोषणा के कॉलम 16 के खिलाफ, यह कहा गया है कि "राशि दाताओं से प्राप्त हुई थी, नाम दर्ज नहीं किए गए थे"।यह एक बहुत ही अस्पष्ट उत्तर था और यह स्थापित नहीं करता कि नोट अध्यादेश की घोषणा से पहले या बाद में प्राप्त हुए थे या नहीं।

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1996] के बाद से।4 एस सी आर।

462

दानदाताओं से राशि एकत्र की गई थी, यह भी दोषी नहीं थी

क.

कि वे सभी गुमनाम रहना चाहेंगे, हालांकि उन्होंने एक अच्छे कारण के लिए दान किया था।

और, तदनुसार उच्च मूल्य के बैंक नोटों के विनिमय मूल्य के भुगतान के लिए न्यास के दावे को खारिज कर दिया।इस तरह के इनकार के खिलाफ ट्रस्ट

भारत सरकार के समक्ष एक अपील की गई जिसे 23 अगस्त, 1979 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उपरोक्त दो आदेश इन रिट याचिकाओं में चुनौती के अधीन हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि जिस तरह से विचाराधीन नोट प्राप्त किए गए थे, उस पर विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को कॉलम संख्या के खिलाफ उसके द्वारा दिए गए विवरणों को रखना चाहिए था।15 और घोषणा के 16 पर्याप्त थे।याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि विमुद्रीकरण अधिनियम के तहत उन पर उन सभी व्यक्तियों के नामों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं डाला गया था जिनसे नोट प्राप्त किए गए थे और न ही वे इन शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य थे।

डी.

रिजर्व बैंक ने कहा कि विचाराधीन नोट अध्यादेश की घोषणा से पहले या बाद में प्राप्त हुए थे।ऐसी सभी परिस्थितियों में,

याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।घोषणा के फॉर्म के कॉलम 15 के तहत, दाखिल करने की आवश्यकता है

ई विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत, राशि को नकद में रखने के कारणों और कॉलम 16 के तहत स्रोत का खुलासा किया जाना है कि नोट कब और कहाँ से घोषणाकर्ता के कब्जे में आए।विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विवरणों के प्रकटीकरण के कारणों की तलाश करना दूर की बात नहीं है।16 जनवरी, 1978 की समाप्ति पर उच्च एफ मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का वैध चलन समाप्त हो जाने के बाद उन्हें दूसरों के कब्जे में स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।इसका मतलब यह है कि उन नोटों को बदलने की लड़ाई और अवसर केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जो तैनात थे।

16 जनवरी, 1978 को भी ऐसा ही किया गया।अतः यह संतोष प्राप्त करने के लिए कि 16 जनवरी, 1978 को या उससे पहले घोषणा करने वाले के पास नोट थे।

जी.

बैंक से आवश्यक जांच करने की अपेक्षा की गई थी और उस संदर्भ में कॉलम 15 और 16 में निर्दिष्ट विवरणों का पूर्ण प्रकटीकरण बिल्कुल आवश्यक था।जैसा कि पहले देखा गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत घोषणा में कॉलम संख्या के खिलाफ कहा गया था।15 और 16 कि "दान द्वारा प्राप्त राशि, उसी के उपयोग के लिए लंबित है" और एच "दाता का नाम दर्ज नहीं किया गया है"।इस प्रकार दिए गए विवरणों में जे. आर. शाह बनाम.

आरबीआइ। [एम. के. मुखर्जी, जे.] 463 को ए के अनुसार संबंधित अधिकारियों का समर्थन नहीं मिलता है।

अधिकारियों, क्योंकि ट्रस्ट के पास एक बैंक खाता था और निकट भविष्य में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, यह बहुत असामान्य लग रहा था कि इसे उपयोग के लिए लंबित हाथों में रखा जाएगा।दानदाताओं के नामों का खुलासा करने में न्यास की विफलता के संबंध में, टिप्पणी यह थी कि यह एक अस्पष्ट उत्तर था और यह स्थापित नहीं करता था कि अध्यादेश से पहले या बाद में नोट प्राप्त हुए थे या नहीं।इसके अलावा, यह देखा गया कि चूंकि राशि दानदाताओं से एकत्र की गई थी, इसलिए यह कारण नहीं है कि सभी दानदाता गुमनाम रहना चाहेंगे, हालांकि उन्होंने एक अच्छे कारण के लिए दान किया था। याचिकाकर्ताओं को भुगतान से इनकार करने के लिए इस तरह से प्रचार किए गए आधारों को अनुचित या अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है ताकि हम इसमें बाधा डालने का अधिकार प्राप्त कर सकें।अतः इन याचिकाओं को भी खारिज किया जा सकता है।

एस.

उपरोक्त निष्कर्षों पर हम सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

याचिका खारिज कर दी गई।

वी. एस.